SHAKTI

PUMPING LIFE

Date: -03.05.2022

To, The Secretary, Listing Department The National Stock Exchange of India Ltd. Exchange plaza, BKC, Bandra (E) Mumbai-MH 400051.	To, The Secretary, Listing Department The BSE Ltd: P.J. Towers, Dalal Street Mumbai- MH 400001.

REF:-(ISIN- INE908D01010) SCRIP CODE BSE-531431, NSE Symbol -SHAKTIPUMP

Sub: - Newspaper Cutting of Published Audited Financial Results for the Quarter and Year ended on 31st March 2022.

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of newspaper clippings containing the extract of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended on 31st March 2022 published on 3rd May, 2022 in The Economic Time (English) and Business Standard (Hindi) Edition.

Kindly take on record the above information for your reference.

Thanking you,

Yours faithfully

For Shakti Pumps (India) Limited

SHAKTI PUMPS (INDIA) LTD.

Ravi Patidar
Company Secretary

Encl:A/a

SHAKTI PUMPS (INDIA) LIMITED

CIN: L29120MP1995PLC009327, Regd. Office & Works: Plot No. 401, 402 & 413, Industrial Area, Sector - 3, Pithampur - 454774, Dist. Dhar (M.P.) INDIA.
Tel.: +91 7292 410500, Fax: +91 7292 410645, E-mail: info@shaktipumps.com, sales@shaktipumps.com, Web: www.shaktipumps.com

वर्ष 15 • अंक 57 • 8 पृष्ठ
• मूल्य 5 रुपये

मंगलवार 3 मई 2022

कोलकाता, चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, मुंबई और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 2

एजीऐंडपी करेगी 18,000 करोड़ रुपये का निवेश

नरेंद्र मोदी पृष्ठ 8

'युद्ध में कोई विजयी नहीं होगा, भारत चाहता है शांति'

डॉलर रु. 76.50 ▲ 10 पैसे | यूरो रु. 80.50 ▼ 40 पैसे | सोना (10 ग्राम) रु 51130 ▼ 717 रु. | सेंसेक्स 56976.00 ▼ 84.90 | निफ्टी 17069.10 ▼ 33.50 | निफ्टी फ्यूचर्स 17084.30 ▲ 15.20 | ब्रेंट क्रूड 103.00 डॉलर ▼ 03.60 डॉलर

एक नज़र

अप्रैल में विनिर्माण गतिविधियों में तेजी

भारत के विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियों में अप्रैल में तेज वृद्धि हुई। एक मासिक सर्वेक्षण में सोमवार को कहा गया कि उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ ही कारखानों को मिलने वाले ऑर्डर बढ़ने और अंतरराष्ट्रीय बिक्री में तेजी के ऐसा हुआ। मौसमी रूप से समायोजित एसऐंडपी ग्लोबल इंडिया विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) अप्रैल में बढ़कर 54.7 हो गया, जो मार्च में मार्च में 54.0 था। कोविड-19 महामारी के चलते लागू प्रतिबंध खत्म होने के बाद मांग बढ़ी है। पीएमआई आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में लगातार 10वें महीने समग्र परिचालन स्थितियों में सुधार देखने को मिला। एसऐंडपी ग्लोबल में अर्थशास्त्र की संयुक्त निदेशक पोलियाना डी लीमा ने कहा कि भारतीय विनिर्माण पीएमआई अप्रैल में सकारात्मक बना रहा और वह मार्च में खोई हुई जमीन को दोबारा हासिल कर रही है। पृष्ठ 4

हरित परियोजनाओं के लिए जर्मनी देगा 10 अरब यूरो

जर्मनी ने भारत को वर्ष 2030 तक हरित परियोजनाओं के लिए 10 अरब यूरो की अतिरिक्त सहायता मुहैया कराने की सोमवार को प्रतिबद्धता जताई। दोनों देशों ने अन्य देशों में संयुक्त परियोजनाओं पर भी मिलकर काम करने पर सहमति जताई। यह चीन के कर्ज आधारित बुनियादी ढांचा वित्त मॉडल से टक्कर का सीधा संकेत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जर्मनी पहुंचे। दोनों पक्षों ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि जर्मनी भारत के साथ अपना वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग और अन्य मदद मजबूत करना चाहता है। इससे भारत को जलवायु और सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी।

स्पाइसजेट घटना के मामले में पूरे बेड़े का निरीक्षण शुरू

भारत के विमानन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सोमवार को घोषणा की कि वह स्पाइसजेट के मुंबई- दुर्गापुर के बीच उड़ान भरने वाले विमान के उतरते समय रविवार को गंभीर वायुमंडलीय विक्षोभ के संपर्क में आने के कारण 17 यात्रियों के घायल होने की घटना के बाद विमानन कंपनी के पूरे बेड़े का निरीक्षण कर रहा है। डीजीसीए ने बताया कि जांच लंबित रहने तक विमान के चालक दल, विमान रखरखाव इंजीनियर (एएमई) और स्पाइसजेट रखरखाव नियंत्रण केंद्र के प्रभावी को रोस्टर से हटा लिया है। डीजीसीए ने कहा कि रविवार को जिस विमान के साथ घटना घटी थी, उसे कोलकाता में खड़ा किया गया है। स्पाइसजेट के बाकी विमान परिचालन में हैं। डीजीसीए ने कहा कि संबंधित विमान चालक दल, एएमई और स्पाइसजेट के रखरखाव नियंत्रण केंद्र के प्रभारी को जांच लंबित रहने तक रोस्टर से हटा लिया है।

टीके के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि किसी भी व्यक्ति को कोविड-19 रोधी टीकाकरण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और न्यायालय ने केंद्र से इस तरह के टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभाव के आंकड़ों को सार्वजनिक करने के लिए कहा है। अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शारीरिक स्वायत्तता और अखंडता की रक्षा की जाती है। पीठ ने सुझाव दिया कि जब तक कोविड संक्रमितों की संख्या कम है तब तक सार्वजनिक क्षेत्रों में टीकाकरण नहीं करवाने वालों पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। पृष्ठ 8

आज का सवाल

क्या देश में स्टार्टअप के लिए बन गया है उपयुक्त माहौल

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या बिजली संकट दूर करने के लिए कोयले की आपूर्ति बढ़ाए सरकार?	हां	80.00%
	नहीं	20.00%

अदाणी, जेएसडब्ल्यू ने लगाई बोली

अंबुजा सीमेंट के लिए लगाई गैर-बाध्यकारी बोली, होल्सिम जल्द सौदा निपटाने के पक्ष में

देव चटर्जी
मुंबई, 2 मई

देश के दो दिग्गज कारोबारी समूह अदाणी और जेएसडब्ल्यू सीमेंट क्षेत्र की दिग्गज अंबुजा सीमेंट्स को खरीदने की होड़ में उतर गए हैं। दोनों ने पिछले हफ्ते ही इस कंपनी के लिए गैर बाध्यकारी बोलियां लगाई हैं। सौदे की करीबी जानकारी रखने वाले एक बैंकर ने बताया कि इस खरीद के लिए रकम के वास्ते दोनों समूहों ने कुछ निजी इक्विटी फंडों के साथ हाथ मिलाया है और यह भी बताया है कि वे सौदा कब तक पूरा करेंगे।

आदित्य बिड़ला समूह की अल्ट्राटेक भी इस दौड़ में है मगर सौदा पूरा होने में देर हो सकती है क्योंकि इसके लिए भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) से मंजूरी की जरूरत होगी, जिसमें समय लगेगा। अंबुजा सीमेंट की प्रवर्तक होल्सिम है और स्विट्जरलैंड की इस कंपनी ने संकेत दिए कि वह सौदा जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है और बोली लगाने वाली जो भी कंपनी सबसे पहले सौदा पूरा करने की बात कहेगी, उसे ही कंपनी सौंप दी जाएगी।

बैंकर ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया, 'गैर बाध्यकारी बोलियों पर फैसला दो बातें देखकर किया जाएगा: पहली, नकद पेशकश कितनी है और दूसरी सौदा पूरा करने में वक्त कितना लगेगा। इसलिए अगर कोई कंपनी बड़ी बोली लगाती है मगर सरकार से मंजूरी हासिल करने में उसे ज्यादा समय लग रहा होगा तो उसे दूसरों से अधिक वजन नहीं दिया जाएगा।' जेएसडब्ल्यू समूह ने अधिग्रहण के लिए अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट की अगुआई में कुछ निजी इक्विटी फंडों से हाथ मिलाया है। अदाणी समूह अपनी नकदी के दम पर और खाड़ी के कुछ सॉवरिन फंडों की मदद से पेशकश कर रहा है।

बैंकर ने बताया कि गैर-बाध्यकारी बोली स्वीकार होने के बाद होल्सिम केवल उन्हीं कंपनियों से बातचीत करेगी और बोली जीतने वाले के सामने अपने सभी आंकड़े खोल देगी।

होल्सिम की ओर से बिक्री की प्रक्रिया गोल्डमैन सैक्स चला रही है। होल्सिम के शेयरधारकों की सालाना बैठक 4 मई को होनी है और उसी समय कंपनी इस बारे में घोषणा भी कर सकती है। बैंकर ने कहा, 'किसी को नहीं पता कि अधिग्रहण पर आखिर में कितना खर्च आएगा मगर मौजूदा बाजार मूल्य के हिसाब से न्यूनतम बोली मूल्य कम से कम 76,000 करोड़ ररुपये होना चाहिए। इसमें खुली पेशकश भी शामिल होगी।' मगर बैंकरों को लगता है कि अदाणी समूह काफी आक्रामक बोली लगाएगा क्योंकि वह सीमेंट उद्योग में दाखिल होना चाहता है।

अंबुजा सीमेंट्स को खरीदने वाला सीमेंट उद्योग में दूसरे स्थान पर काबिज हो सकता है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट्स की मौजूदा उत्पादन क्षमता सालाना 1.4 करोड़ टन की है। उत्तर भारत में 15 लाख टन और पूर्वी भारत में 70 लाख टन क्षमता विस्तार पूरा होने के साथ अंबुजा की कुल क्षमता 4 करोड़ टन सालाना की हो जाएगी। इसकी सहायक इकाई एसीसी की सालाना उत्पादन क्षमता 3.3 करोड़ टन है, जिससे अगले कुछ वर्षों में कंपनी की कुल उत्पादन क्षमता 7.3 करोड़ टन हो जाएगी।

अंबुजा सीमेंट्स के अधिग्रहण की दौड़

- दोनों समूहों ने सौदे के लिए निजी इक्विटी फंडों से किया है गठजोड़
- अल्ट्राटेक सीमेंट भी अंबुजा को खरीदने की दौड़ में मगर सीसीआई का फंसा है पेच
- होल्सिम नकद पेशकश और सौदे के जल्दी पूरा होने के आधार पर विजेता बोली चुन सकती है

कुछ ऋण खाते बेचेगी एलऐंडटी फाइनैंस

देव चटर्जी और अभिजित लेले
मुंबई, 2 मई

- कंपनी 41,713 करोड़ रुपये के अपने ऋण खातों का कुछ हिस्सा बेचने के लिए बैंकों से कर रही बात
- कर्ज घटाने और खुदरा ऋण पर ध्यान देने के लिए लोन बुक बेचना चाह रही कंपनी
- एलऐंडटी ने म्युचुअल फंड कारोबार को भी बेचने के लिए किया है समझौता

निर्माण एवं अभियांत्रिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी लार्सन ऐंड टुब्रो की सहायक इकाई एलऐंडटी फाइनैंस होल्डिंग्स अपने रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचा फाइनैंस के ऋण खातों को बेचने की योजना बना रही है। इस कदम का मकसद कर्ज कम करना और रिटेल ग्राहकों पर ध्यान देना है। वित्तीय सेवा कंपनी अपने ऋण खाते बेचने के लिए भारतीय स्टेट बैंक सहित कई बैंकों के साथ बात कर रही है।

एलऐंडटी फाइनैंस का रियल एस्टेट खाता इस साल मार्च तक घटकर 11,210 करोड़ रुपये रह गया है और बुनियदी ढांचा फाइनैंस का खाता सिकुड़कर 30,521 करोड़ रुपये रह गया है। मार्च 2021 में समाप्त वित्त वर्ष में रियल एस्टेट फाइनैंस की लोन बुक 12,945 करोड़ रुपये और बुनियादी ढांचा फाइनैंस की लोन बुक 37,543 करोड़ रुपये थी।

एक बैंकर ने नाम नहीं छापने का आग्रह करते हुए कहा, 'एलऐंडटी फाइनैंस समय के साथ अपना रियल एस्टेट खाता समेट सकती है। मार्च तिमाही में इसकी रियल एस्टेट उधारी 13 फीसदी घटी है जबकि बुनियादी ढांचा फाइनैंस की उधारी साल भर पहले के मुकाबले 19 फीसदी घटी है। हालांकि रिटेल लोन बुक में इस दौरान वृद्धि देखी गई।'

घटनाक्रम के जानकार सूत्रों ने कहा कि ऋण खाते बेचने से प्रवर्तक कंपनी एलऐंडटी को अपना कर्ज कम करने में मदद मिलेगी। एकीकृत स्तर पर पिछले साल सितंबर तक एलऐंडटी का कर्ज 1.27 लाख करोड़ रुपये था। एलऐंडटी फाइनैंस ने अपना म्युचुअल फंड कारोबार बेचने के लिए एसएचबीसी ऐसेट मैनेजमेंट (इंडिया) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। (शेष पृष्ठ 4 पर)

एचडीएफसी का लाभ 16 फीसदी बढ़ा

आवास ऋण कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड का जनवरी-मार्च, 2022 को समाप्त बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही का एकल शुद्ध लाभ 16 फीसदी की वृद्धि के साथ 3,700 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इससे एक साल पहले की इसी अवधि में कंपनी ने 3,180 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। एचडीएफसी ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 12,308.46 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले की समान अवधि में 11,707.53 करोड़ रुपये थी। समूचे वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी का शुद्ध लाभ 13,742 करोड़ रुपये रहा जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में यह 12,027 करोड़ रुपये रहा था। चौथी तिमाही में एकीकृत आधार पर कंपनी का शुद्ध लाभ 21.6 फीसदी बढ़कर 6,892 करोड़ रुपये हो गया, जो जनवरी-मार्च, 2021 में 5,669 करोड़ रुपये था। पृष्ठ 3

देश में यूनिकॉर्न का सैकड़ा हुआ पूरा

शिवानी शिंदे
बेंगलूरु, 2 मई

भारत में एक अरब डॉलर से अधिक मूल्यांकन वाली स्टार्टअप (यूनिकॉर्न) का आंकड़ा सौ के पार पहुंच गया है। स्टार्टअप और यूनिकॉर्न पर नजर रखने वाली इकाई इंक42 के अनुसार वित्त तकनीक खंड की स्टार्टअप इकाई 'ओपन' 100वीं यूनिकॉर्न बनी है। मोबाइल विज्ञापन कंपनी इनमोबी यूनिकॉर्न होने का दर्जा हासिल करने वाली पहली भारतीय स्टार्टअप थी। उसने 2011 में यह कारनामा किया था। देश में यूनिकार्न का शतक लगने की खुशी स्टार्टअप के साथ ही सत्ता के गलियारों में भी दिखी। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया, 'भारत ने अपने अनोखे अंदाज में यूनिकॉर्न इकाइयों का शतक पूरा किया है। भारत का मतलब है नया विचार, नवाचार और निवेश।'

सिकोया इंडिया के प्रबंध निदेशक राजन आनंदन ने कहा कि देश के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा, 'देश में पहली यूनिकॉर्न 2011 में सामने आई थी। अब 11 साल बाद भारत 100वीं भारतीय यूनिकॉर्न का स्वागत कर रहा है।'

इंक42 ने कहा कि इन सभी यूनिकॉर्न ने 333 अरब डॉलर मूल्यांकन पर 90 अरब डॉलर रकम जुटाई है। इनमें फ्लिपकार्ट और बैजूस का मूल्यांकन सर्वाधिक आंका गया है। हालांकि एक महीने बाद 100वीं यूनिकॉर्न का आगाज रकम जुटाने के लिहाज से बिना किसी बड़ी घोषणा के हो रहा है। 2021 से यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल करने वाली स्टार्टअप इकाइयों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वेंचर इंटेलिजेंस के अनुसार 2021 में हर महीने कम से कम 3-4 स्टार्टअप यूनिकॉर्न की जमात में शामिल हुईं, जिससे इनकी संख्या बढ़कर 33 हो गई।

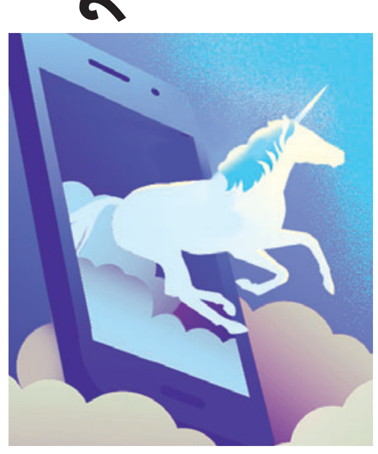

- यूनिकॉर्न की जमात में शामिल होने वाली 100वीं स्टार्टअप बनी 'ओपन'
- इनमोबी ने 2011 में देश की पहली यूनिकॉर्न बनने का तमगा हासिल किया
- इंक42 के अनुसार सभी यूनिकॉर्न ने कुल 333 अरब डॉलर के मूल्यांकन पर 90 अरब डॉलर की जुटाई है पूंजी

जहां तक पूंजी जुटाने की बात है तो 2021 में कुल 1,579 सौदों के माध्यम से 42 अरब डॉलर रकम जुटाई गई। आयरन पिलर फंड के अनुसार यूनिकॉर्न की संख्या अब तेजी से बढ़ रही है और इनमें आधी को तो यह उपलब्धि हासिल करने में पांच वर्षों से भी कम का समय लगा। इनमें करीब 8 प्रतिशत स्टार्टअप साढ़े सात साल से भी कम समय में यूनिकॉर्न बन गईं। देश की 100वीं स्टार्टअप इकाई होने की उपलब्धि हासिल करने वाली वित्त-तकनीक क्षेत्र की इकाई ओपन ने आईआईएफएल सहित मौजूदा निवेशकों टेमासेक, टाइगर ग्लोबल और 3वन4 कैपिटल से 5 करोड़ डॉलर रकम जुटाई है।

CONSOLIDATED FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2022

TOTAL REVENUE	EBIDTA	PBT	PAT	EPS
₹ 1184.68 Cr.	₹ 116.59 Cr.	₹ 82.34 Cr.	₹ 64.82 Cr.	₹ 35.26

STATEMENT OF AUDITED CONSOLIDATED & STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2022

(Rs. in Lacs, unless otherwise stated)

S. No	Particulars	Consolidated					Standalone				
		Quarter Ended on			Year ended on		Quarter Ended on			Year ended on	
		March 31, 2022	December 31, 2021	March 31, 2021	March 31, 2022	March 31, 2021	March 31, 2022	December 31, 2021	March 31, 2021	March 31, 2022	March 31, 2021
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from operation (Net)	38,647.74	27,087.20	32,111.24	118,467.65	93,343.26	36,574.61	26,048.11	30,989.47	113,469.09	89,029.05
2	Net Profit/(loss)for the period before tax and exceptional items	2,862.00	2,022.56	4,355.23	8,234.20	11,124.63	2,298.60	2,015.35	3,502.10	6,867.12	9,321.00
3	Net Profit/(loss)for the period before tax after exceptional items	2,862.00	2,022.56	4,355.23	8,234.20	11,124.63	2,298.60	2,015.35	3,502.10	6,867.12	9,321.00
4	Net Profit/(loss) for the period after tax	2,196.24	1,478.61	3,049.90	6,481.60	7,558.64	1,711.74	1,504.59	2,325.18	5,559.40	6,116.97
5	Total Comprehensive Income for the period	2,191.80	1,611.52	3,035.17	6,659.83	7,493.46	1,696.24	1,500.85	2,385.31	5,531.18	6,163.64
6	Equity share capital (Face Value: Rs.10/- per share)	1,838.02	1,838.02	1,838.02	1,838.02	1,838.02	1,838.02	1,838.02	1,838.02	1,838.02	1,838.02
7	Earnings per equity share (EPS) of Rs.10/- each for continued and discontinued operations										
	(1) Basic	11.95	8.04	16.59	35.26	41.12	9.31	8.19	12.65	30.25	33.28
	(2) Diluted	11.95	8.04	16.59	35.26	41.12	9.31	8.19	12.65	30.25	33.28

* The Company operates its business through operating segments, representing our business on the basis of geographies which are India & Overseas.
* The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on May 02, 2022.
* The board of directors have recommended a dividend of Rs. 2/- (20%) par equity share of Rs. 10/- Each. for FY 21-22. The final dividend is subject to approval by shareholders at the ensuing Annual general Meeting of the Company.
* Figures for the corresponding previous periods have been regrouped/rearranged, wherever necessary.

For Shakti Pumps (India) Limited
Sd/-
Dinesh Patidar
Managing Director
(DIN 00549552)

Place: Pithampur
Date: 02nd May, 2022

देश का सोलर पम्प, शक्ति पम्पस्

SHAKTI PUMPS (INDIA) LIMITED

CIN : L29120MP1995PLC009327, Regd. Office & Works: Plot No. 401, 402, 413, Industrial Area, Sector - 3, Pithampur - 454774, Dist.- Dhar (M.P.) - INDIA. Fax: +91-7292-410645
E-mail: info@shaktipumps.com, cs@shaktipumpsindia.com Web: www.shaktipumps.com, Toll Free No. India: 1800 103 5555, Tel.: +91-7292 410500

VIGILANCE-R

Vaccination Can't be Imposed; Curbs on Unvaxxed Must be Reasonable: SC

Apex court asks states to scale down vaccine mandates with an option to reimpose them if the threat emerges again

Samanwaya.Rautray
@timesgroup.com

New Delhi: No one can be forced to take vaccines in violation of one's bodily integrity and personal autonomy, the Supreme Court has ruled. "Bodily integrity is protected under Article 21 (right to life). No one can be forced to get vaccinated," the bench said in a ruling on Monday.

"Persons who are keen not to be vaccinated on account of personal beliefs or preferences can avoid vaccination, without anyone physically compelling them to be vaccinated." However, SC said the state can impose some restrictions on the unvaccinated in the interest of the general public, but they would have to be reasonable and proportionate to threat the unvaccinated pose to the community. The bench accordingly directed all state governments to scale back their vaccine mandates to ensure that they were reasonable. If the situation warranted, governments could reimpose them to prevent transmission of the virus, it said.

Vaccine Mandates by States

MADHYA PRADESH: One would have to be vaccinated to get rations

DELHI: No govt employee to be allowed in if they are not vaccinated

MAHARASHTRA: People have to be vaccinated to enter public spaces and public transport

TAMIL NADU: Unvaccinated cannot enter public spaces such as schools and cannot even sit for exams

Various state governments have come up with their own vaccine mandates. Some have restricted access to public spaces to the unvaccinated. Some others have said that they would be denied government jobs. These were challenged in SC. The bench dubbed those which restrict the unvaccinated from public spaces as disproportionate and sought a review of such mandates in view of the falling Covid-19 threat.

Governments, central and state, failed to prove that the unvaccinated spread the virus more than the vaccinated. There is no data to warrant curbs on them accessing public spaces, the bench said.

Till the numbers are low, we suggest that no restriction is imposed on individuals on access to public areas or these be recalled if already not done, it said. The bench did not find any unconstitutionality in the Centre's extant vaccination policy. They were as per industry practices and standards followed the world over, including the decision to vaccinate children. "The court is satisfied that the current vaccine policy cannot be said to be manifestly arbitrary."

The bench asked the government to make public all information received so far on adverse effects from vaccinations. This would only promote public confidence in the vaccinations, it said. "Subject to the privacy of individuals… all data must be made available to the public without further delay," it said. This would cover data regarding previous trials and any future trials. The bench refused to examine the procedures followed by DCGI's special expert committee in approving vaccines.

TO APPEAR FOR MANDATORY FOREIGN MEDICAL GRADUATE EXAM

MHA Okay Needed for Pak Med Degree Holders After 2018

Rahul.Tripathi
@timesgroup.com

ET was the first to report on April 27 that the govt was considering a ban on Pakistan medical degrees

New Delhi: Medical students who secured degrees from Pakistan universities after December 2018 will need security clearances from the home ministry to appear for Foreign Medical Graduate Examinations (FMGE), the National Medical Commission and Dental Council of India have said in directives issued on Monday.

The move follows reports that medical seats in Pakistan were 'allocated' to various separatist organisations in J&K, who charged money from aspirants and used it to fund terrorism. ET was the first to report, in its April 27 edition, that the Centre was considering a proposal to derecognise medical degrees from Pakistan.

"All concerned are advised not to travel to Pakistan for pursuing medical education. Any Indian national/overseas citizen of India who intends to take admission in MBBS/BDS or equivalent medical course in any medical college of Pakistan shall not be eligible for appearing in FMGE or seeking employment in India on the basis of educational qualifications acquired in Pakistan except those who had joined Pakistan degree colleges/institutions before December 2018 or later after obtaining security clearance from MHA till date," the NMC statement said. The Dental Council of India too issued a similar statement.

Migrants and their children who have acquired medical degree or higher education in Pakistan and have been awarded Indian citizenship would, however, continue to be eligible for appearing in FMGE/NEXT or seeking employment in India after obtaining security clearance from the home ministry, the NMC and DCI said.

JIGNESH MEVANI BAIL CASE

Gauhati HC Stays Barpeta Court Observations On Assam Police

Bikash.Singh@timesgroup.com

Guwahati: The Gauhati HC has stayed two observations made by the Barpeta session's court while it granted bail to Gujarat Independent MLA Jignesh Mevani. The HC said that the Assam government was free to challenge the bail order and fixed the next hearing for May 27.

Assam advocate general Deajit Lon Saikia told journalists in Guwahati on Monday that HC has served a notice to Mevani to appear on May 27. "The court has asked that the notice be delivered to Mevani through registered post and has allowed even a messenger from Assam Police or Gujarat Police to deliver the notice to Mevani," Saikia said. Justice Devashis Baruah accepted the state's argument that certain remarks on the police force not only demoralised it but also casts aspersion on the force.

"The learned sessions judge…made certain observations to the effect which had no relevance to the consideration of the bail application," the HC said while staying the observations. The HC, however, added, "the instant order may not be construed in any manner as a stay to the grant of bail by the learned sessions judge."

MNS Chief Drops Plan to Hold 'Maha Aartis' on Eid

Krishna.Kumar
@timesgroup.com

Mumbai: The Maharashtra Navnirman Sena (MNS) has cancelled plans to hold 'Maha Aartis' on Akshaya Tritiya — which falls on Tuesday, the same day as Eid.

Addressing his supporters, MNS chief Raj Thackeray tweeted: "Tomorrow is Eid... The Muslim community should celebrate this festival in happiness. Do not celebrate Akshiya Tritiya by holding Maha Aartis anywhere (in the state). We do not want to create obstacles in anyone's festival."

Maharashtra govt has decided to file a case against MNS chief for his 'communal' speech

The MNS chief also seemed to put his call for putting up loudspeakers blaring Hanuman Chalisa outside Mosques on May 4 on hold. "The issue of loudspeakers is not religious but social and what to do about it will be revealed tomorrow through Twitter," he tweeted.

The MNS call for the Maha Aartis to be held on the same day as Eid had put the Maharashtra government and the police machinery on alert. This is because Maha Aartis done in the past have led to violence.

A report of the BN Sri Krishna Commission, formed in the wake of one of the worst Hindu-Muslim riots (in 1992-93), had faulted the government and the police for letting the BJP and the Shiv Sena organise Maha Aartis in Mumbai, identifying it as one of the main reasons for the riots.

NCP Chief's Kin Refuses to Accept Award from Koshyari

Our Political Bureau

Mumbai: Rajendra Pawar, a nephew of NCP chief Sharad Pawar, on Monday refused to take an award from Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari. Rajendra Pawar is the son of NCP chief's eldest brother late Appasaheb Pawar and father of Rohit Pawar, an MLA from the Karjat-Jamkhed constituency.

Governor Koshyari was to confer the Dr Panjabrao Deshmukh Krishi Ratna Award in Nashik on Monday, when Rajendra Pawar refused to attend the ceremony. Speaking to reporters later, he said, "There has been a systematic attempt to hurt Maharashtra's pride in the last few days. Great people like Mahatma Phule and Savitribai, who opened the doors of education to everyone, have been the subject of very slanderous comments. If people, who don't know about Maharashtra's history and encourage people to create anarchy like situation in the state, are the ones giving an award, how can I accept it?"

While Pawar did not take the name of Governor, he was indirectly referring to the latter as Koshyari had made comments on Phule and Savitribai recently.

Rahul Gandhi in Nepal on 5-Day Private Visit

Kathmandu: Congress leader Rahul Gandhi arrived in Nepal on Monday on a five-day private visit to the country. Gandhi, who arrived at the Tribhuvan International Airport Monday evening, is likely to visit some tourist spots during his stay. According to The Kathmandu Post newspaper, the Congress leader is in Kathmandu to attend the wedding of his Nepali friend Sumnima Udas, who is a former CNN correspondent.—**PTI**

Prashant Kishor Hints At Political Plunge from Bihar

New Delhi: Days after he turned down Congress party's offer to make him a member of its empowered committee, political strategist Prashant Kishor has said he is turning a new page after ten years of a "rollercoaster ride in participating in the democracy" to help shape pro-people policies. Kishor may reveal his plan in detail from Patna on Thursday.—Vasudha Venugopal

AVAILABLE STRUCTURAL STEEL EQUIPMENT

Available Structural Steel and Unused & Uninstalled Equipment from **THERMAL POWER PLANT 660 MW X 2** with Pulverized Coal fired Super Critical Boilers. From site at **LANCO VIDHARBHA THERMAL POWER PLANT**, 11th Milestone, Belgaon-Mandwa Road, District-Wardha, Maharashtra - 442201.

1) Good condition MS sheets / Structure / Pipes / Angles / Channels.
2) Re-Rolling materials & Heavy MELTING SCRAP in bulk.
3) SS sheets /Pipes. **4)** ESP **5)** New gratings/Chequered plates.

Interested parties may inspect and contact:
+91 9819480631 / 9867313028

Request for Proposal (RFP)
for appointment of Consultant for Formulating Branding & Positioning Strategy for Global City Gurugram

HSIIDC invites proposals for above services through an online transparent competitive bidding process.

For schedule of bidding process and other required details, the interested parties are requested to refer Request For Proposal Document available on the website **www.hsiidc.org.in** and **https://etenders.hry.nic.in**.

Amendments, addenda, corrigendum, etc., will be uploaded on the website only.

Bid Submission: 16.05.2022

HSIIDC
Haryana State Industrial & Infrastructure Development Corporation Limited
A State Government Undertaking
Regd. Office: C-13 & 14, Sector-6, Panchkula, **Ph.** 0172-2590481-83,
E-mail: contactus@hsiidc.org.in, **Website:** hsiidc.org.in, **Fax:** 2590474
CIN: U29199HR1967SGC034545 | /mdhsiidc

THE TIMES OF INDIA
LET TRUTH PREVAIL

BENNETT UNIVERSITY
THE TIMES GROUP

AN MBA WITH 100% PLACEMENT GUARANTEE

Indian logistics sector is expected to reach **$380 Billion** mark by 2025*

Now it's your turn to be one of them with 2 Year
MBA Logistics & Supply Chain Management Program
at Bennett University

Knowledge Partner: TIMESPRO

PROGRAM HIGHLIGHTS

Sector-Focussed **Curriculum**

Industry-Recognised **Certifications**

Convenient Fee Payment Schedule

Full Time, Paid, **On-The-Job-Training** In Semester IV

Skills & Competencies Mapped To Industry Requirements

ADMISSIONS OPEN FOR AY 2022 -23
MBA LOGISTICS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PROGRAM
LAST DATE TO APPLY: 15TH MAY 2022

For Admission Enquiries
1800 103 8484 | 8860309257 | Apply Now: bennett.edu.in

PREPARING INDIA TO MOVE WITH THE TIMES

T & C Apply
* Source : www.financialexpress.com

SHAKTI PUMPING LIFE

SHAKTI SOLAR PUMPS.
INNOVATION THAT BENEFITS ALL

CONSOLIDATED FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2022

TOTAL REVENUE ₹ 1184.68 Cr. | EBIDTA ₹ 116.59 Cr. | PBT ₹ 82.34 Cr. | PAT ₹ 64.82 Cr. | EPS ₹ 35.26

STATEMENT OF AUDITED CONSOLIDATED & STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2022

(Rs. in Lacs, unless otherwise stated)

S. No	Particulars	Consolidated					Standalone				
		Quarter Ended on			Year ended on		Quarter Ended on			Year ended on	
		March 31, 2022	December 31, 2021	March 31, 2021	March 31, 2022	March 31, 2021	March 31, 2022	December 31, 2021	March 31, 2021	March 31, 2022	March 31, 2021
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from operation (Net)	38,647.74	27,087.20	32,111.24	118,467.65	93,343.26	36,574.61	26,048.11	30,989.47	113,469.09	89,029.05
2	Net Profit/(loss) for the period before tax and exceptional items	2,862.00	2,022.56	4,355.23	8,234.20	11,124.63	2,298.60	2,015.35	3,502.10	6,867.12	9,321.00
3	Net Profit/(loss) for the period before tax after exceptional items	2,862.00	2,022.56	4,355.23	8,234.20	11,124.63	2,298.60	2,015.35	3,502.10	6,867.12	9,321.00
4	Net Profit/(loss) for the period after tax	2,196.24	1,478.61	3,049.90	6,481.60	7,558.64	1,711.74	1,504.59	2,325.18	5,559.40	6,116.97
5	Total Comprehensive Income for the period	2,191.80	1,611.52	3,035.17	6,659.83	7,493.46	1,696.24	1,500.85	2,385.31	5,531.18	6,163.64
6	Equity share capital (Face Value: Rs.10/- per share)	1,838.02	1,838.02	1,838.02	1,838.02	1,838.02	1,838.02	1,838.02	1,838.02	1,838.02	1,838.02
7	Earnings per equity share (EPS) of Rs.10/- each for continued and discontinued operations										
	(1) Basic	11.95	8.04	16.59	35.26	41.12	9.31	8.19	12.65	30.25	33.28
	(2) Diluted	11.95	8.04	16.59	35.26	41.12	9.31	8.19	12.65	30.25	33.28

* The Company operates its business through operating segments, representing our business on the basis of geographies which are India & Overseas.
* The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on May 02, 2022.
* The board of directors have recommended a dividend of Rs. 2/- (20%) par equity share of Rs. 10/- Each. for FY 21-22. The final dividend is subject to approval by shareholders at the ensuing Annual general Meeting of the Company.
* Figures for the corresponding previous periods have been regrouped/rearranged, wherever necessary.

For Shakti Pumps (India) Limited
Sd/-
Dinesh Patidar
Managing Director
(DIN 00549552)

Place: Pithampur
Date: 02nd May, 2022

देश का सोलर पम्प, शक्ति पम्पस्

SHAKTI PUMPS (INDIA) LIMITED

CIN : L29120MP1995PLC009327, Regd. Office & Works: Plot No. 401, 402, 413, Industrial Area, Sector - 3, Pithampur - 454774, Dist.- Dhar (M.P.) - INDIA. Fax: +91-7292-410645
E-mail: info@shaktipumps.com, cs@shaktipumpsindia.com Web: www.shaktipumps.com, Toll Free No. India: 1800 103 5555, Tel.: +91-7292 410500

VIGILANCE-R